



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 972]
No. 972]नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 27, 2003/कार्तिक 5, 1925
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 27, 2003/KARTIKA 5, 1925सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2003

का.आ. 1233(अ).—केन्द्रीय सरकार, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (2000 का 29) की धारा 67 के साथ पठित सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) की धारा 47(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्यों की सरकारों के साथ परामर्श से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का पुनर्गठन करने के संबंध में उन सरकारों द्वारा भेजी गई स्कीम का अनुमोदन करती है और उक्त स्कीम को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

भाग 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल राज्य सड़क परिवहन निगम (पुनर्गठन) आदेश, 2003 है।

(2) यह 31 अक्टूबर, 2003 को प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं- इस आदेश में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) “अधिनियम” से सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 (1950 का 64) अभिप्रेत है;

(ख) “नियत दिन” से वह दिन अभिप्रेत है जिसको यह आदेश प्रवृत्त होता है;

- (ग) “तुलन पत्र” से महालेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश द्वारा संपरीक्षित विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का 31 मार्च, 2002 को यथाविद्यमान तुलन पत्र अभिप्रेत है;
- (घ) “विद्यमान निगम” से अधिनियम के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अभिप्रेत है और जो नियत दिन के ठीक पूर्व कार्य कर रहा है और प्रवर्तन में है;
- (ङ) उत्तरांचल के पुनर्गठित निगम के संबंध में उत्तर प्रदेश के पुनर्गठित निगम के “विहित अनुपात” से 86.66 : 13.34 का अनुपात अभिप्रेत है;
- (च) “पुनर्गठित निगम” से पैरा 3 के अधीन यथापुनर्गठित विद्यमान निगम अभिप्रेत है;
- (छ) “उत्तरवर्ती निगम” से, यथास्थिति, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के पुनर्गठित निगम अभिप्रेत है;
- (ज) “उत्तरवर्ती प्राधिकारी” से उत्तरवर्ती उत्तरप्रदेश राज्य और उत्तरवर्ती उत्तरांचल राज्य अभिप्रेत है;

भाग 2

विद्यमान निगम का पुनर्गठन

3. विद्यमान निगम के प्रचालन से कतिपय क्षेत्रों का अपवर्जन और पुनर्गठन - (1) दोनों उत्तरवर्ती निगमों की पारस्परिक सहमति के सिवाय नियत दिन से, विद्यमान निगम उत्तरांचल राज्य के राज्य क्षेत्र में कार्य करना बंद कर देगा और नियत दिन से विद्यमान निगम उत्तरांचल सरकार द्वारा पुनर्गठित किया गया समझा जाएगा।
- (2) नियत दिन को केन्द्रीय सरकार द्वारा विद्यमान निगम को उपलब्ध कराई गई पूंजी उत्तरवर्ती निगमों को विहित अनुपात में पुनः आबंटित की जाएगी।

भाग 3

आस्तियों, अधिकारों और दायित्वों का विभाजन

4. 31 मार्च, 2002 को विभाजित की जाने वाली आस्तियां, अधिकार और दायित्व - तुलन पत्र में यथादर्शित, जो पैरा 3 में वर्णित हैं उससे भिन्न, विद्यमान निगम की आस्तियों, अधिकारों और दायित्वों को इस भाग में अन्तर्विष्ट सिद्धांतों के अनुसार उत्तरवर्ती प्राधिकारियों के बीच विभाजित किया जाएगा।

5. आस्तियों, अधिकारों और दायित्वों का विभाजन - (1) ऐसे मुद्दे जिन पर उत्तरवर्ती निगमों और उत्तरवर्ती प्राधिकारियों के बीच मतभेद हो गया है उन पर पारस्परिक करार के अनुसार करवाई की जाएगी।

(2) आस्तियां और दायित्व जिनके अन्तर्गत बसें, तालिका, नियत आस्तियां और क्षेत्र कर्मचारीवृन्द, पद तथा विद्यमान निगम के विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थित सम्मान है, नियत दिन को 'जैसा है जहाँ है' आधार पर विभाजित किए जाएंगे।

(3) ऐसा क्षेत्र कर्मचारीवृन्द जिनके नियुक्ति प्राधिकारी विद्यमान निगम के क्षेत्र या जोन या डिपो के अधिकारी हैं, उस संबंधित उत्तरवर्ती निगम द्वारा आमेलित किए जाएंगे जिसमें उक्त जोन या क्षेत्र या डिपो अवस्थित है।

(4) मुख्यालये कर्मचारीवृन्द की बाबत उन्हें पदों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, दोनों उत्तरवर्ती निगमों में से किसी में भी पद ग्रहण करने का विकल्प दिया जाएगा।

(5) मुख्यालय तथा मुख्यालय द्वारा समर्थित ऐसी केन्द्रीय इकाइयों के कर्मचारियों और अधिकारियों से, जिनके नियुक्ति प्राधिकार उत्तरांचल क्षेत्रों में कार्यरत अधिकारियों में निहित नहीं हैं, विकल्प लिया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों को जिन्होंने उत्तरांचल के निगम के लिए विकल्प दिए हैं, पदों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए, अंतरित किया जाएगा और उन्हें उक्त उत्तरांचल निगम में आमेलित किया गया समझा जाएगा।

(6) प्रतिनियुक्ति पर अग्रसर अधिकारियों के मामले में, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति दायित्व प्रतिनियुक्ति की अवधि की सीमा तक उधार लेने वाले संगठन द्वारा वहन किए जाएंगे। दोनों उत्तरवर्ती निगमों में से किसी में स्थायी रूप से आमेलित अधिकारियों की बाबत ऐसे दायित्व संबंधित उत्तरवर्ती निगम द्वारा वहन किए जाएंगे।

(7) ऐसे व्यक्तियों को देय पेंशन से भिन्न संदाय जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उत्तरांचल निगम के गठन तक उस उत्तरवर्ती निगम द्वारा किए जाएंगे जहाँ वह क्षेत्र स्थित है जहाँ से कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ था।

- (8) उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित विद्यमान निगम की सभी संपत्तियां विद्यमान निगम के मुख्यालय की इकाई की संपत्तियां समझी जाएंगी और वे भी विहित अनुपात में विभाजित की जाएंगी।
- (9) चूंकि क्षेत्रों की आस्तियां और दायित्व 'जैसा है जहाँ है' आधार पर अंतरित की जा रही हैं अतः अंतर कार्यालय समायोजनों का मुद्दा औपचारिक विभाजन के समय लेखों के अंतिम परिनिर्धारण के दौरान विनिश्चित किया जाएगा।
- (10) विद्यमान निगम और मुख्यालय द्वारा समर्थित केन्द्रीय इकाइयों की आस्तियों (जिसके अन्तर्गत भूमि और भवन भी हैं) और दायित्वों का विभाजन विद्यमान बाजार मूल्य के आधार पर किए गए पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् 31 मार्च, 2002 को यथा विद्यमान लेखों के आधार पर विहित अनुपात में होगा।
- (11) उत्तरांचल के तीन क्षेत्रों के लिए 5.4 करोड़ रुपए के ऋण का उपयोग, 1.4 करोड़ रुपए के सिवाय जो अनन्य रूप से उत्तरांचल निगम के लिए उपयोग किया गया है, विहित अनुपात में विभाजित किया जाएगा।
- (12) 9 नवंबर, 2000 से उत्तरवर्ती निगमों के गठन तक संग्रह किए गए कर की वास्तविक रकम की बाबत दायित्व की गणना की जाएगी। इसी प्रकार विद्यमान निगम द्वारा किसी भी उत्तरवर्ती प्राधिकारी को किए गए वास्तविक संदाय की गणना की जाएगी। संबंधित उत्तरवर्ती निगमों के अंश का प्रभाजन दोनों उत्तरवर्ती निगमों के क्षेत्रों से संग्रह किए गए कर और उस वास्तविक संदाय के मुकाबले किए गए वास्तविक संदाय के आधार पर अनुपाततः किया जाएगा और यदि तीन क्षेत्रों की बाबत जमा की गई रकम का उत्तरांचल के उन तीनों क्षेत्रों द्वारा संग्रहीत रकम से कुल अनुपात लगाए गए कर से संदत्त कर के वास्तविक अनुपात से कम है तो रकम में अंतर को उत्तरवर्ती निगमों द्वारा और विपर्ययन समायोजित किया जाएगा।
- (13)(क) विद्यमान निगम के विभाजन के पश्चात् उत्तरवर्ती निगमों के बीच ऋण दायित्व निम्न प्रकार होगा (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विकास बोर्ड और पीसीआरए से लिए गए ऋण के वितरण के लिए दोनों राज्यों के बीच पहले ही सहमति हो चुकी है) :-

(रुपए करोड़ में)

	उत्तरांचल	उत्तर प्रदेश	कुल
1. किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए ऋण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विकास बोर्ड	---	9.00	9.00
2. पी सी आर ए	0.01	0.10	0.11
3. 9.11.2000 से 31.3.2000 तक अभिप्राप्त ऋण (बसों की संख्या के अनुपात में *			
(क) 102 : 802	6.58	51.76	58.34
(ख) 97 : 807	6.26	52.08	58.34
4. 9.11.2000 से पूर्व प्राप्त ऋण का अतिशेष (बसों की 'आयु' के अनुपात में अर्थात् 13.34 : 86.66)	8.65	56.18	64.83
5. 5.40 करोड़ के राज्य ऋण का संदाय	1.93	3.47	5.40

* दिए गए दो विकल्पों के अनुसार दोनों राज्य बसों की वास्तविक संख्या का समाधान करेंगे।

(ख) ऋण का पुनः संदाय निम्न प्रकार समायोजित किया जाएगा ।

(i) राज्य सरकारों को संदेय ऋण दायित्वों का अंश संबंधित निगमों द्वारा संबंधित राज्य सरकारों को संदेय होगा ।

(ii) वित्तीय संस्थाओं के दायित्व निम्न रीति में संदेय करने के लिए समायोजित किए जाएंगे, अर्थात्:-

(क) उत्तरांचल राज्य सड़क परिवहन निगम वित्तीय संस्थाओं के दायित्व का अपना सम्पूर्ण अंश जीवन बीमा कंपनी को संदाय करेगा ।

(ख) जीवन बीमा निगम को शेष दायित्व और अन्य सभी वित्तीय संस्थाओं का दायित्व उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश निगम द्वारा संदेय होगा ।

(iii) अन्य दायित्वों की बाबत वास्तविक लेखों की परीक्षा के पश्चात् और ऐसे दायित्वों में किन्हीं परिवर्तनों के मामले में, वह ऋण से भिन्न दायित्वों में समायोजित किया जाएगा ।

भाग 4

विधिक कार्यवाहियां

6. नियत दिन को, ऐसे अन्तर्राज्यीय राष्ट्रीयकृत रूटों की बाबत जो न्यायाधीन थे, उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश निगम द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी और ऐसे रूटों की बाबत विधिक कार्रवाई करते समय उत्तरवर्ती उत्तरांचल निगम को ऐसे रूटों की बाबत जो उत्तरांचल के राज्य क्षेत्र में आते हैं, सम्यक रूप से सूचित किया जाएगा ।

[फा. सं. आर टी-17020/3/2003-टी]

आलोक रावत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th October, 2003

S.O. 1233(E).— In exercise of the powers conferred by section 47(A) of the Road Transport Corporation Act, 1950 (64 of 1950), read with section 67 of Uttar Pradesh Reorganisation Act, 2000 (29 of 2000), the Central Government, in consultation with the Governments of the States of Uttar Pradesh and Uttaranchal, approves the scheme forwarded by the respective Governments relating to reorganisation of the Uttar Pradesh State Road Transport Corporation and for the purpose of giving effect to the said scheme, hereby makes the following Order, namely :-

**PART - I
PRELIMINARY**

- 1 **Short title and commencement-** (1) This Order may be called the Uttar Pradesh and Uttaranchal State Road Transport Corporation (Reorganisation) Order, 2003.
(2) It shall come into force on the 31st October, 2003.
2. **Definitions-** In this order unless the context otherwise requires:-
 - (a) "Act" means the Road Transport Corporations Act, 1950, (64 of 1950);
 - (b) "appointed day" means the day on which this Order comes into force;
 - (c) "balance sheet" means the balance sheet of the existing Uttar Pradesh State Road Transport Corporation as on the 31st March, 2002 audited by Auditor General, Uttar Pradesh;
 - (d) "existing Corporation" means the Uttar Pradesh State Road Transport Corporation established under the Act and functioning and operating immediately before the appointed day;
 - (e) "prescribed ratio" of the reconstituted Corporation of Uttar Pradesh in relation to the reconstituted Corporation of Uttaranchal means the ratio of 86.66 : 13.34;
 - (f) "reconstituted Corporation" means the existing Corporation as re-constituted under paragraph 3;
 - (g) "successor Corporation" means the reconstituted Corporations of Uttar Pradesh and Uttaranchal, as the case may be;
 - (h) "successor authorities" means the successor States of Uttar Pradesh and Uttaranchal.

PART - II
RE-CONSTITUTION OF THE EXISTING CORPORATION

3. **Exclusions of certain areas from the operation of the existing Corporation and re-constitution:-** (1) Save as otherwise mutually agreed by both the successor Corporations, from the appointed day the existing corporation shall cease to function in the territories of State of Uttaranchal and, as from the appointed day, the existing Corporation shall be deemed to have been reconstituted by the Government of Uttaranchal.
- (2) The capital provided to the existing Corporation by the Central Government as on the appointed day shall be re-allotted to the successor Corporations in the prescribed ratio

PART- III
DIVISION OF ASSETS, RIGHTS AND LIABILITIES

4. **Assets, rights and liabilities to be divided as on the 31st March, 2002** - The assets, rights and liabilities of the existing corporation, other than those dealt with in paragraph 3, as shown in the balance sheet shall be divided between the successor authorities in accordance with the principles contained in this part.
5. **Division of assets, rights and liabilities-** (1) Issues on which consensus has been reached between the successor corporations and successor authorities, action as per mutual agreement shall be taken.
- (2) The assets and liabilities including buses, inventory, fixed assets and field staff, posts and stores located in the various regions of the existing corporation shall be divided on the basis of 'as is where is basis' as on appointed day.
- (3) The field staff whose appointing authority are officers of the region or zone or depot of the existing corporation, shall be absorbed by the respective successor Corporation in which the said zone or region or depot is located.
- (4) In respect of the Headquarters staff, option would be provided to them to join either of the two successor corporations, subject to availability of posts.
- (5) Options shall be taken from the employees and officers of the Headquarters and the Headquarters supported central units, whose appointing authority is not vested in the officers working in Uttaranchal regions. Such employees and officers, who opt for the corporation of Uttaranchal, shall be

transferred, subject to availability of posts, and they will be treated as absorbed in the said corporation of Uttaranchal.

- (6) In case of officers proceeding on deputation, the pension and other retirement liabilities shall be borne to the extent of period of deputation by the loanee organization. As regards officers permanently absorbed in either of the two successor corporations, such liabilities shall be borne by the respective successor Corporations.
- (7) The payments other than pension due to those who have retired, till the formation of the corporation of Uttaranchal, shall be made by the successor Corporation, where the region from where the employee had retired, is situated.
- (8) All the properties of the existing Corporation situated outside Uttaranchal and Uttar Pradesh will be considered to be the properties of headquarter unit of the existing corporation and these shall also be divided in the prescribed ratio.
- (9) Since the assets and liabilities of the regions are being transferred on 'as is where is basis', the issue of inter-office adjustments shall be decided during final settlement of accounts at the time of formal bifurcation.
- (10) The division of assets (including land and building) and liabilities of headquarter of the existing corporation and the Central Units supported by Headquarter would be in the prescribed ratio on the basis of the accounts as on the 31st March, 2002 after revaluation done on the prevailing market value.
- (11) The utilization of the loan of Rs.5.4 crores for the three regions of Uttaranchal shall be divided in the prescribed ratio except for Rs.1.4 crores which has been exclusively used for Corporation of Uttaranchal.
- (12) The liability in respect of actual amount of tax collected from the 9th November, 2000 till the formation of successor Corporations shall be computed. Similarly, the actual payment made by the existing Corporation to either of the successor authorities shall also be computed. The apportionment of the share of respective successor Corporations shall be pro rata on the basis of actual payment made vis-à-vis tax collected from the regions of two successor corporations and actual payment made i.e. if the total ratio of amount deposited in respect of three regions to that collected by the three regions of Uttaranchal is

less than the actual ratio of tax paid to the tax generated, then the difference in amount shall be adjusted by successor Corporations and vice versa.

- (13) (a) After division of the existing Corporation, the loan liability between successor Corporations shall be as under (the distribution of loans taken from National Capital Region Development Board and Petroleum Conservation Research Association have already been agreed upon between the two States):-

(Rs. Crores)

	Uttaranchal	Uttar Pradesh	Total
1. Loan for any specific area National Capital Region Development Board	---	9.00	9.00
2. Petroleum Conservation Research Association.	0.01	0.10	0.11
3. Loans obtained from 9.11.2000 to 31.3.2000 (in the ratio of the number of the buses* (a) 102:802 (b) 97:807	6.58 6.26	51.76 52.08	58.34 58.34
4. The balance of loans received before 9.11.2000 (in the ratio of the age of buses i.e. 13.34:86.66)	8.65	56.18	64.83
5. Payment of state loans of 5.40 crores	1.93	3.47	5.40

*The two States are to reconcile the exact number of buses as per the two options given.

(b) Loan repayment shall be adjusted as follows:-

- (i) The share of loan liabilities payable to State Governments shall be payable by respective corporations to respective State Governments.

(ii) The liabilities towards financial institutions shall be adjusted to be payable in the following manner, namely:-

- (a) Uttaranchal State Road Transport Corporation shall pay its entire share of financial institutions liability to Life Insurance Corporation.
- (b) The remaining liability to Life Insurance Corporation and liability of all other financial institutions shall be payable by successor Corporation of Uttar Pradesh.

(iii) If after the examination of actual accounts in respect of other liabilities and in case of any changes occur in such liabilities, the same shall be adjusted against liabilities other than loans.

PART – IV

LEGAL PROCEEDINGS

6. On the appointed day, necessary legal action shall be taken by the successor Corporation of Uttar Pradesh in respect of interstate nationalised routes which were subjudice and while taking legal action in respect of such routes, the successor Corporation of Uttaranchal shall be duly kept informed in respect of such routes which lie within the territory of Uttaranchal.

[F. No. RT-17020/3/2003-T]

ALOK RAWAT, Jt. Secy.